जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 17 संख्याः 205 प्रभात जालोर, बुधवार 2 नवम्बर, 2022 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

इंग्लैण्ड के नॉर्थ यॉर्कशायर में ऑस्प्री के घोंसले में दो चूज़े देखे गए हैं। अमेरिका में तो यह घटना न्यूज़ नहीं बनती लेकिन यॉर्कशायर में 200 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। यह बदलती हवा का संकेत है कि, 1916 में अंधाधुंध शिकार के कारण लुप्त हुए ऑस्प्री पक्षी इंग्लैण्ड के कई क्षेत्रों में वापसी कर रहे हैं। अब ये कम्ब्रिया, नॉर्थम्बरलैंड और नॉर्थ एण्ड वैस्ट वेल्स में प्रजनन करते नज़र आ रहे हैं तथा एक ट्रस्ट उन्हें ईस्ट एंगलिया में पुनः बसाने की कोशिश कर रहा है। सन् 1840 से 1916 के बीच ब्रिटेन के तटों के पास इन पक्षियों को बड़े पैमाने पर मारा गया क्योंकि ऐसी धारणा थी कि, ये सामन और ट्राउट फिश संग्रहण को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बदलते नजरिए की वजह से रैप्टर्स व अन्य पक्षियों के संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए, उन्हीं दिनों ऑस्प्री का एक जोड़ा स्कैण्डिनेविया से उड़कर स्कॉटलैण्ड आ गया। उसके बाद से यहाँ की निर्जनता तथा भारी मात्रा में मछलियों से युक्त जलाशयों व जलधाराओं के कारण स्कॉटलैण्ड में इनकी आबादी बढ़ती गई और 2018 में हुई गणना में यहाँ ऑस्प्री के 250 जोड़े मिले। स्वयमेव हुई इस पक्षी की वापसी के बाद उम्मीद की गई कि, आगामी 100 सालों में समूचे इंग्लैंड में ऑस्प्री की प्राकृतिक रुप से वापसी हो जाएगी। इसलिए विभिन्न वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इसके पुनर्वास के काम में जुट गए। लैस्टरशायर एंड रटलैण्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, जो रटलैण्ड ऑस्प्री प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, ने लगभग दो सौ साल में पहली बार ऑस्प्री की इग्लैंड में वापसी करवाई। इसके तहत 1966-2001 के बीच जो 64 स्कॉटिश ऑस्प्री चिक्स छोड़े गए थे उनमें से अब, वयस्क हो चुके 26 ऑस्प्री पक्षियों ने लगभग 200 चूज़े पाल-पोसकर बड़े कर लिए हैं। इन सबने अब रटलैण्ड वॉटर नाम के एक जलाशय के चारों तरफ पार्क में घर बनाया है जहाँ मछलियाँ भरपूर मात्रा में हैं। रटलैण्ड वॉटर रिज़र्व के मैनेजर जोई डेविस ने इसे भारी सफलता की संज्ञा दी है। ऑस्प्री प्रवासी पक्षी हैं और पश्चिमी अफ्रीका और सहारा के पार तक जाते हैं।

बाहर की शान्ति भ्रमित करती है, राजस्थान की राजनीतिक स्थिति के बारे में

गहलोत को हटाने का निर्णय लिया जा चुका है, केवल टाइमिंग के लिये ''फाइन टयूनिंग'' हो रही है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। राजस्थान मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी में जहां उच्चतम स्तर पर आधिकारिक चुप्पी है, वहीं सूत्र कहते हैं कि अन्दरूनी रूप से पार्टी नेतृत्व यही चाहता है कि मुख्यमंत्री को बदला जाना चाहिए। अब बहस सिर्फ इसके उचित समय को लेकर है, जिसे तलाशा जा रहा है।

सुविज्ञ सूत्र कहते है कि अशोक गहलोत को अवगत करवा दिया गया है कि उन्हें सम्मानजनक ढंग से पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह काफी सीनियर नेता हैं और पार्टी इस मुद्दे पर कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती।

लेकिन ज्ञात हुआ है कि गहलोत ने इससे इन्कार कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वह इस्तीफा देने के इच्छुक नहीं हैं।

पता चला है कि राहुल गांधी ने पार्टी के सीनियर नेताओं से कहा है कि गहलोत को किसी भी हालात में विदा होना चाहिए और यदि इस प्रक्रिया में सरकार चली जाती है तो भी कोई बात नहीं। राहुल ने सीनियर नेताओं से पूछा कि गहलोत को हटाने की क्या प्रतिक्रया होगी। जब उन्हें यह बताया गया कि ऐसा होने पर गहलोत सरकार गिरा सकते हैं तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सरकार गिर जाने दीजिए।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ''राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत सरकार है ना कि कांग्रेस सरकार। अतः तर्क यह है कि यदि गहलोत सरकार गिरती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्थिति कांग्रेस सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

यह बयान यह दर्शाता है कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है और वास्तविकता यह है कि गहलोत के व्यवहार को लेकर निराशा आक्रोश है जो कि अब पार्टी पर अपने ओनरशिप राइट्स के दावे कर रहे हैं।

ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व अशोक गहलोत की गलतफहमी दूर करना चाहता है।

- गहलोत से कहा जा चुका है कि, वे एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अतः उन्हें पद की शालीनता को ध्यान में रखते हुए, इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी भी मु.मंत्री बदलने के मामले को एक सार्वजनिक तमाशा नहीं बनाना चाहती।
- गहलोत ने हाईकमान की यह राय अस्वीकार कर दी है, तथा हाईकमान को कह दिया है कि, वे इस्तीफा देने की कतई इच्छा नहीं रखते।
- दूसरी ओर, राहुल गांधी का स्पष्ट सोच है, गहलोत को जाना ही चाहिए, चाहे इससे राजस्थान में पार्टी की सरकार गिर ही क्यों न जाये।
- राहुल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछा कि, अगर गहलोत को हटाया गया तो इसका क्या नतीज़ा निकलेगा। जवाब मिला कि, इससे पार्टी की सरकार गिरा सकते हैं गहलोत। राहुल का जवाब था, इससे फर्क नहीं पड़ता।
- एक वरिष्ठ नेता का इस मुद्दे पर कहना था, ''वैसे भी राजस्थान में गहलोत की सरकार है, पार्टी की सरकार नहीं और अगर गहलोत की सरकार गिरती है, तो कांग्रेस की सरकार सत्ता में आयेगी।''

तीन नवम्बर को तेलंगाना की विधानसभा सीट के लिये मतदान होगा

-लक्ष्मण वेंकट कुची -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। तेलंगाना के मुनुगोडे विधानसभा सीट के उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में भारी हिंसा देखी गई। सत्तारुढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टी.आर.एस.) और विपक्षी भाजपा के कार्यकर्ताओं के आपसी टकराव से संकेत मिलता है कि चुनाव किस कदर महत्वपूर्ण हैं दोनों पार्टियों के लिए। इसने नतीजे को तेलंगाना की राजनीति की भावी की दिशा माना जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के साथ राज्य में विधानसभा चुनाव भी होंगे।

संयोगवश मुनुगोडे सीट मौजूदा विधायक कांग्रेस के कोमातिरे राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की वजह से रिक्त हुई है। वे अपनी सीट से भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं तथा उनका मुकाबला टी.आर.एस. विधायक कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी और कांग्रेस के पलावई श्रावंती रेड्डी से है।

सत्तारुढ़ टी.आर.एस. और भाजपा का यहां कड़ा मुकाबला है तथा दोनों दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी ताकि कांग्रेस की सीट हथिया सकें। कांग्रेस भी अपने दलबदलू विधायक को सबक सिखाने की रणनीति पर काम कर रही है। टी.आर.एस.और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन का आखिरी मिनट तक सड़कों पर रोड शो करते हुए बिताया जिसकी वजह कई बार दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में टकराव भी हुआ।

टी.आर.एस. और भाजपा के कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी हुई तथा लाठी सरियों के साथ हिंसक संघर्ष भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हालांकि, एक सीट पर जीत व हार का सरकार व विपक्ष के विधायकों की संख्या पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर, टी.आर.एस. व भाजपा ने अपना सब कुछ झोंक दिया है, इस चुनाव में।
- इस उप चुनाव में जीत/हार से मालूम पड़ेगा, आगामी 2024 के विधानसभा व संसद के चुनाव में कौन हावी रहेगा, भाजपा या टी.आर.एस.।
- भाजपा को बहुत उम्मीद है कि, तेलंगाना में उसका भविष्य उज्जवल है और वह टी.आर.एस. को पछाड़ कर, सरकार भी बना सकती है विधानसभा चुनाव के बाद, और फिर आम चुनाव में भी काफी सांसद भेज सकेगी लोकसभा में।

ई.वी.एम. पर चुनाव चिन्ह

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ई.वी.एम. पर पार्टी के चुनाव चिन्ह की बजाय प्रत्याशी की फोटो, उम्र और शैक्षणिक योग्यता दिखाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए पूछा कि चुनाव चिन्ह लगाने में गलत क्या है।

चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित के नेतृत्व वाली बैंच जनहित याचिका में की गई इस मांग से अप्रभावित नज़र आई कि राजनैतिक पार्टी की जगह पर प्रत्याशी को प्रोजैक्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि ''चुनाव राजनैतिक पार्टी से सम्बंधित होते हैं। मतदाता एक राजनैतिक पार्टी से सम्बंधित व्यक्ति को वोट देते हैं उसकी पार्टी को अनदेखा नहीं किया जा सकता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ई.वी.एम. पर पार्टियों के चुनाव चिन्ह दर्शाए जाने को गैर कानूनी करार देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और पूछा कि इसमें आखिर गलत क्या है।

सरकार ने अपना शिकंजा और कसा सोशल मीडिया पर

नये आई.टी. रूल्स के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को, अपने प्लेटफार्म पर कोई मैसेज/न्यूज़ डालने से पहले उस मैसेज की स्क्रीनिंग कर, हटाना है या रखना है, का निर्णय लेना होगा

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। मोरबी में पुल ढहने की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी और गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में जोर-शोर से चल रहे चुनाव प्रचार पर मीडिया के फोकस के बीच आई.टी. रूल्स, 2022 के लिए 28 अक्टूबर को आई अधिसूचना पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया।

संशोधित नियमों में दो महत्वपूर्ण व ठोस बदलाव किए गए हैं। पहला तो यह है कि नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने प्लेटफॉर्म्स पर परोसी जा रही विषय वस्तु की पूर्व स्क्रीनिंग करे। इस प्रकार से सोशल मीडिया कम्पनियों पर आपत्तिजनक सामग्री हटाने की जिम्मेदारी डाल दी गई है। पूर्व के आई.टी. रूल्स, 2021 के अनुसार सोशल मीडिया कम्पनियों को अपने इन्टरनल ग्रिवैन्स रिड्रेसल मैकेनिज़म पर कोई शिकायत प्राप्त होने के बाद ही अपनी साइट्स से आपत्तिजनक कन्टैन्ट हटाना होता था।

संशोधित आई.टी. नियमों में जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है वह है नए नियमों की अधिसूचना जारी होने के तीन माह के भीतर ग्रिवैन्स अपीलेट कमेटी (जी.ए.सी) का गठन किया जाना।

इसका मतलब यह है कि जो लोग सोशल मीडिया कम्पनी के इन्टरनल ग्रिवैन्स रिड्रैसल मैकेनिज़म के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, वे जी.ए.सी. में अपील कर सकते हैं। जी.ए.सी. के निर्णय सोशल मीडिया कम्पनियों और यूजर्स दोनों पर लागू होंगे। नए नियमों में जी.ए.सी. को यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया है कि सोशल मीडिया पर कौनसा कन्टैन्ट जा सकता है और कौनसा नहीं।

वर्ष 2021 के आई.टी. एक्ट ने सरकार को पहले ही यह अधिकार दिया हुआ है कि वह जिस कन्टैन्ट को आपत्तिजनक समझे उसे सोशल मीडिया से हटा सकती है। इन शक्तियों का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अब तक सोशल मीडिया कंपनियों की प्रसारण के पश्चात् शिकायत आने पर ही आपत्तिजनक मैसेज हटाना है हटाने की जिम्मेवारी होती थी।
- नये रूल्स के तहत एक ग्रीवैन्स अपील कमेटी का गठन किया जायेगा, तथा किसी विवाद में इस कमेटी का निर्णय फाइनल होगा तथा दोनों पार्टियां, शिकायत कर्ता व सोशल मीडिया, को निर्णय मानना होगा।

'ठगों की पार्टी आप'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. सम्बित पात्रा ने धोखेबाज सुकेश चन्द्रशेखर द्वारा गत 7 अक्टूबर के दिल्ली के लैफ्टिनैंट गवर्नर विनय कुमार सक्सैना को लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- आप पार्टी को धोखेबाजों व ठगों की पार्टी करार देते हुए भाजपा प्रवक्ता सम्बित पात्रा ने तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चन्द्रशेखर का पत्र जारी किया, जिसमें उसने दावा किया है कि, उसने आप पार्टी को 10 करोड़ रूपए प्रोटैक्शन मनी के रूप में और 50 करोड़ रूपए राज्यसभा सीट के लिए दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को लताड़

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण रुख अपनाते हुए एक मामले की लिस्टिंग में अत्यधिक विलम्ब को लेकर अपनी खुद की रजिस्ट्री से ही सोमवार को स्पष्टीकरण मांगा। यह मामला सभी प्रक्रियात्मक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को फटकारा और नोटिस जारी कर दिया, जब उन्हें यह पता लगा कि, जो केस उनके सामने आया वह डेढ़ साल पहले ही लिस्टिंग के लिए तैयार था पर रजिस्ट्री उसे दबाए बैठी थी।

फिल्म स्टार चिरंजीवी एक बार फिर आंध्र की राजनीति में अवतरित होंगे!

आंध्र के तेलुगू सिने जगत में वे उतने बड़े हैं जितने अमिताभ बच्चन हिन्दी व रजनीकांत तमिल पिक्चरों में

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। इस समय फिल्म दीवाने राज्य आंध्र प्रदेश में, सारी चर्चाएं मेगास्टार चिरंजीवी के एक बार पुनः राजनीति में प्रवेश पर केन्द्रित हैं। ज्ञातव्य है कि चिरंजीवी, तेलुगू फिल्म जगत में अमिताभ बच्चन तथा रजनीकांत की ही तरह बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं तथा दो तेलुगू भाषी राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं।

2008 में, चिरंजीवी राजनीति में आये थे तथा उन्होंने अपनी राजनैतिक पार्टी, प्रजा राज्यम पार्टी (पी.आर.पी.) बनाई थी और तीसरी ताकत के रूप में विधानसभा चुनावी भी लड़ा था लेकिन कुछ खास नहीं कर पाये थे। वे उस समय के एकीकृत आंध्र प्रदेश में 294 में से केवल 18 सीटें ही जीत सके थे। लेकिन उनके चुनाव मैदान में आने से चुनावों की जटिलता जरूर बढ़ गई थीं। इनके आने से कांग्रेसी मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी का फिर से चुना जाना सुनिश्चित हो गया था क्योंकि चिरंजीवी ने कांग्रेस विरोधी वोट काटे थे तथा कांग्रेस की जीत में मदद की थी। वस्तुतः उन दिनों यह सर्वविदित था कि चिरंजीवी की राजनैतिक भूमिका का पटकथा-लेखन तथा निर्देश वाई.एस.आर. ने किया था, जैसा कि बाद की घटनाओं से सिद्ध भी हो गया था।

चिरंजीवी दो सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिनमें से वे एक ही सीट पर हार गये थे। इस एक सीट सहित, केवल 18 सीटें जीतने के बाद, इस मेगा स्टार ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया तथा इसके पुरस्कार स्वरूप वे डॉ. मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिये गये, वर्ष 2014 में हुई कांग्रेस की घोर पराजय के बाद, चिरंजीवी आंध्र प्रदेश की राजनीति में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- 2008 में चिरंजीवी ने अपनी प्रजा राज्यम पार्टी बनायी व विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़े किये थे।
- हालांकि, उनके 18 उम्मीदवार ही विजयी हुए, पर, एन्टी कांग्रेस वोटों को विभाजित कर उन्होंने कांग्रेस को बहुमत पाने का रास्ता तय करवाया।
- कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी का कांग्रेस में विलय करवाकर, वे राजनीति की दृष्टि से सुप्त अवस्था में चले गये।
- पर, उनके छोटे भाई पवन कल्याण, जो स्वयं सिने स्टार हैं, ने अपनी पार्टी, जना सेना बनायी, जो भाजपा के नज़दीक बतायी जाती है।
- चिरंजीवी लगातार मूक संदेश दे रहे हैं कि, वे पुनः राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं, संभवतया अपने छोटे भाई की पार्टी के माध्यम से।
- सार्वजनिक जिज्ञासा यह है कि, वे भाजपा के नज़दीक तो रहेंगे, पर, क्या वाय.एस.आर. कांग्रेस से दूरी बना सकेंगे, क्योंकि, उन्होंने वर्तमान मु.मंत्री के पिता वाय.एस.आर. को 2008 में मु.मंत्री बनवाने में, बहुत अहम् भूमिका अदा की थी।

वायर न्यूज़ के पक्ष में मीडिया एकजुट

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। प्रैस क्लब ऑफ इंडिया, प्रैस एसोसिएशन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन और वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन ने वायर न्यूज वैबसाइट के संस्थापकों व इसके स्टाफ पर की गई कार्यवाही की संयुक्त बयान में घोर निंदा की। रविवार को वायर न्यूज के संस्थापक व स्टाफ के घरों पर रेड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- प्रैस क्लब ऑफ इंडिया, प्रैस एसोसिएशन, डैल्ही, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और अन्य कई संस्थाओं ने भाजपा की आई.टी. सैल प्रमुख की शिकायत पर हुई इस कार्यवाही का कड़ा विरोधी किया है।